LOK SABHA

Friday, July 21, 1967/Asadha 30, 1889 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Import of Sulphur through S. T. C.

*1291. **Shri Madhu Limaye:**
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri S. M. Banerjee:
Shri George Fernandes:

Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 324 on the 7th April, 1967 and state:

(a) whether any penalty was imposed on U.S firms as promised by Shri Manubhai Shah, former Minister of Commerce, in the statement made by him in Lok Sabha on 21st November, 1966;

(b) whether Government intend to make investigation into the antecedents and standing of the foreign firms with which agreements are proposed to be signed as a pre-condition for awarding big contracts;

(c) whether this practice will be prescribed both for the departments and the Public Undertakings under Government;

(d) whether Government intend to publish the reports on the antecedents along with the agreements;

(e) whether the sum of Rs. 75,000 recovered from the U.S. firm includes all the expenses incurred by Government representatives who travelled abroad on this mission, the cost of opening the letter of credit and loss due to the blow that India's prestige suffered abroad, and

(f) if the reply to part (e) above be in the negative, the steps Government propose to take to recover the losses?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) to (f). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) By negotiation an agreement has been arrived at whereby the firm has agreed to pay a sum of Rs. 75,000 for the settlement of the claims of the S.T.C

(b) and (c). This procedure is already in vogue.

(d) It will not be appropriate to publish reports on the antecedents along with the agreements as the reports on antecedents provided by banks and others are confidential.

(e) The sum of Rs. 75,000 adequately covers all expenses incurred by the Corporation in connection with the deal. No representative of the Corporation travelled abroad specifically for the deal in question. An officer who happened to be in U.S.A. for other work was asked to look into the prospects of imports materialising under the deal. No net expense was incurred in establishing the Letter of Credit.

(f) Does not arise.

श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के (बी) और (सी) भागों के उत्तर में कि जिन लोगों के साथ यह कट्टेपट करते हैं क्या उन की पृष्ठभूमि आदि के बारे में आने वाले

का वर्षा है केडिट आदि के बारे में, कोई जांच पड़ताल की जाती है उस का जवाब देते हुए मंत्री जी ने यह कहा है कि :

"This procedure is already in vogue."

अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ओवेलिन्ड के साथ सल्फर का जो कट्रैक्ट किया जिस के बारे में सियाल सिंह से अपने टेलेक्स में जो कुछ कहा है उस को मैंने सदन की मेज पर रक्खा है और वह यह है कि .

"I shall come to the inevitable conclusion that Ovalind has entered into a contract with us just for speculative purposes of their own."

इस टेलेक्स की रोशनी में क्या मंत्री महोदय सदन को बतलायेंगे कि इस फर्म के साथ यह कट्रैक्ट करने के पहले क्या उन्होंने बैंक रिफरेंस किये थे, या अमरीका की किसी कम्पनी से, जिन में से एक का नाम है डन ब्रैड स्ट्रीट, उन्होने जानकारी हासिल की थी, या जो वहा पर हमारा दूतावास है उस से जानकारी हासिल की थी कि इस तरह का बड़ा कट्रैक्ट वह पूरा कर सकते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, अभी माननीय सदस्य ने जिस कम्पनी का नाम लिया है उन से जाच करने के लिए हम ने अपने दूतावास को कट्रैक्ट पर दस्तखत करने के पहले सूचना दी थी और एम० टी० सी० जो एक और कारोबार एच० एच० ई० सी० है उसका एक नुमाइन्दा वहा रहता है । उनसे भी हम ने कहा था कि वह इसकी जाच करें । उस की रिपोर्ट आने के पहले अप्लायन्स इडस्ट्रीज के लोग आये और उन्होने हर तरह का इत्मीनान दिलाया । मैंने सदन में इस कट्रैक्ट के बारे में कहा है कि यह एम० टी० सी० का एक अजीब कट्रैक्ट था और उस जमाने में सल्फर की कमी थी । पूरी दुनिया में कमी थी और हमारे देश को बहुत आवश्यकता थी । इस लिये हम ने पूरी कोशिश की कि जहां से भी जो कुछ भी सल्फर मिल सके वह हम मंगा कर यहां दें । इसमें हमें उम्मीद थी कि वहां से सल्फर आ सकता है । हम ने इस बात की पूरी कोशिश और बहुत जल्दी भी की ।

माननीय सदस्य जो कहते हैं, और मैं उन से सहमत हूं, कि यह बेहतर होता अगर पूरी रिपोर्ट आ जाने तक हम रुकते और रुक कर पूरी तरह उस को देखते । लेकिन चूंकि रिपोर्ट नहीं आई थी इस लिये हम ने उस में ऐसे क्लाजेज रक्खे जिन की वजह से एस०टी०सी० को रुपये का नुकसान नहीं हुआ मैं ने जो वक्तव्य सदन में रखा है उस में कहा है कि 75 हजार रुपये हमें उन से मिलेंगे जिसमें उन्होंने 7,500 रु० यानी 10 फी-सदी भेज दिया है । बाकी यहां भेजेंगे ।

सवाल इस में इतना है कि इस में हमारा कोई नुकसान हुआ है या नहीं ? जहां तक मैं ने कागज देखे हैं, ऐसा नहीं मालूम होता है कि हमारा कोई नुकसान हुआ हो । हमारा जो पूरा खर्च हुआ है उस के बारे में लोगों का अन्दाज है कि 10 हजार रुपये से ज्यादा नहीं हुआ, और 75 हजार रुपया हमें मिल रहा है । इसमें कम्पेन्सेशन का भी एलिमेंट है हम ने जो राय ली उस में हमारे वकील ने कहा कि हम का मुकदमा नहीं चलाना चाहिये । मैं ने इस के बारे में कई मर्तबे जवाब दिया है लेकिन शायद मैं माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट नहीं कर पाया हूं । मैं आप से कहना चाहता हूं कि हमारा कोई इरादा इस में से किसी चीज को छिपाने का नहीं है । और कोई गलती हुई है जो कि असाधारण है, तो उस की पूरी जाच होनी चाहिये और मैं पुरी सख्ती के लिये तैयार हूं । आप जैसे भी मुनासिब समझें । मैं कह सकता हूं अब कि चार पाच माननीय सदस्य, जिन के नाम आप मुझे भेजें, अनौपचारिक रूप से मेरे साथ बैठ कर वह कागज देख सकते हैं और अपने को सन्तुष्ट कर सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं ।

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय ने जो सुझाव दिया है वह अच्छा है लेकिन वह बात हमारे और मंत्री के बीच में नहीं है। उनका सुझाव ठीक है, पांच माननीय सदस्यों की एक बाकायदा संसदीय कमेटी बना दी जाये।

श्री दिनेश सिंह : मैं ने कमेटी के लिये नहीं कहा। पांच माननीय सदस्य अनौपचारिक रूप से बैठ कर देख लें।

श्री मधु लिमये : यह मामला हमारे और मंत्री महोदय के बीच में नहीं है।

श्री दिनेश सिंह : मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह यह कि अगर कोई गलती मिलती है तो उस की जाच के तरीके हैं और वह होंगे।

श्री मधु लिमये : आप कमेटी की बात पर सोचिये। जो डन ब्रैड स्ट्रीट की रपट है वह मैं प्रमाणित कर के आप की इजाजत से टेबल पर रख रहा हूं। आप उसे देखने के बाद मेज पर रखने की इजाजत दीजिये ताकि सदन को पता चले कि इस तरह की रपट के आधार पर यह कट्रेक्ट नहीं हो सकता। सभा पटल पर रख दी गयी।

[पुस्तकालय में रख दी गयी। देखिये संख्या LT-1151/67]

मेरा दूसरा सवाल है कि क्या यह बात सही है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने जब निर्णय लिया अगस्त के अंत में या सितम्बर के शुरू में पिछले साल, कि जो सल्फर आयात किया जायेगा वह स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की मार्फत होगा उस वक्त क्या यह स्थिति थी कि सल्फर 40 या 45 डालर फी टन आ रहा था और जब उन्होंने अपने हाथ में इसे ले लिया तब 55 डालर प्रति टन खरीदने का कंट्रेक्ट किया है? मैं केवल जानकारी चाहता हूं कि क्या अगस्त के महीने में 40-45 डालर प्रति टन मिल रहा था सल्फर और उन के अपने हाथ में लेने के पश्चात् जो कंट्रेक्ट उन्होंने किया है—मैं एफ० ओ० बी० की बात कर रहा हूं—वह 55 डालर का किया है?

श्री दिनेश सिंह : जो सूचना मेरे पास है उस के अनुसार 55 डालर का जो कंट्रेक्ट हम ने उन के साथ किया था वह जितने भी आफर थे उन के हिसाब से सब से अच्छा आफर था कई कमेटियों ने इस की जांच की थी।

श्री मधु लिमये : मैं यह पूछ रहा था कि इस कट्रेक्ट को करने के पहले और इस व्यापार के सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने के एक महीना पहले, पन्द्रह दिन पहले, आठ दिन पहले क्या हिन्दुस्तान में जो सल्फर आयात हो रहा था वह 40-45 डालर प्रति टन के दाम से हो रहा था?

श्री दिनेश सिंह : इस का जवाब इस कटेस्ट में सही नहीं होगा, इस लिये मैंने इस के बारे में नहीं कहा कि कितने पर वह बिक रहा था और कितने पर पुराने कंट्रेक्ट से आ रहा था। इस का सवाल नहीं है। उस समय कितने पर नया बिक रहा था और कितने पर हम बाहर से मंगा सकते थे, इस का महत्व है।

Shri S. M. Banerjee: Sir, even the very eloquent and very elaborate statement of the hon. Minister has not convinced me that the deal is not a shady deal. I have actually read once again the long statement given in this House on 21st November, 1966 by Shri Manubhai Shah in which he said that he had only Rs. 38,000 in his life—public life and private life. Then he threw a challenge to my hon. friend, Shri Madhu Limaye and others.

श्री मधु लिमये : मैं उस वक्त सदन में नहीं था, नहीं तो छोड़ता नहीं।

Shri S. M. Banerjee: Sir, I would like to know, in view of the criticism against Shri Manubhai Shah, the ex-Minister, and against this particular firm, which was manufacturing ladies shoes and not sulphur at all, whether any probe will be made possible by

the hon. Minister by a parliamentary committee? I want a parliamentary committee to go into this.

Shri Dinesh Singh: I have already submitted what I had to say. It is for this House to decide as they wish to deal with this matter. A parliamentary committee in the initial stage might give an impression that a public sector enterprise—which I think is doing well; it may have certain difficulties—has been trying to do something which the parliament as a whole has not approved. What I am suggesting is, let some hon. Members sit with me and if they are satisfied that something has gone wrong, then you may decide what you want to do.

Shri Ranga: Sir, it is within your the Public Accounts Committee

Shri Ranga: Sir, it is within your power to refer such controversial matters, instead of leaving it to a few Members of this House and the Minister, to one of the three committees that are there and which are working under your direction—the Public Accounts Committee, the Estimates Committee and the Public Undertakings Committee.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : सरकार की जो आयात निर्यात की नीति है वह कुछ अजीब सी है। यह बात सुनने में आई है कि औरतों का जूता बनाने वाली कम्पनी से हम सल्फार लाते हैं और हिन्दुस्तान में स्टील आयात करने के जो लाइसेंस हैं वे फिल्म हीरोज को देते हैं। मंत्री महोदय ने उत्तर देते हुए यह कहा है कि दस हजार रुपये का हमें इस मामले में नुकसान हुआ है और 75 हजार रुपया हमें मिला है, इसलिए कुल मिला कर हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि यह जो 65000 हमें ज्यादा मिला है फारेन एक्सचेंज में या डालर में मिला होगा तो मंत्री महोदय ऐसी ही कार्रवाइयां या ऐसे ही कांट्रेक्ट एस० टी० सी० के जरिये और भी क्यों नहीं करवाते हैं जिस में दस हजार का नुकसान हमें हो जाए और 65 हजार हम लोगों को ज्यादा मिले ?

श्री दिनेश सिंह : मैं आशा करता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन और तजारत करके पैसा कमायेगी। एक बात मैं साफ कर दूं चूंकि माननीय सदस्य ने उसका जिक्र कर दिया है। जो 75,000 है इसका एक तिहाई हिस्सा हमें डालर में मिलेगा, दो तिहाई हिस्सा रुपये में मिलेगा।

श्री एस० ए० जोशी : मैं डी० आर० के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ रहा हूं। सवाल में यह पूछा गया है कि ऐसे जो कांट्रेक्ट किये जाते हैं उनके एटीसीडेंट्स देखे जाते हैं और क्या गवर्नमेंट इन एटीसीडेंटस की रिपोर्ट छपवायेगी ? आपने अपने जवाब में कहा है कि लोगों के सामने हम यह नहीं रख सकते हैं कि क्योंकि बैंकों वगैरह में जो पैसा होता है वह कान्फिडेंशल होता है। वह कान्फिडेंशल होता है तो उसको रहने दीजिये। लेकिन क्या आप इस सदन की एक ऐसी कमेटी सिर्फ इस के लिए नहीं बल्कि सब के लिए, जो भी कांट्रेक्ट एस० टी० सी० द्वारा किये जाते हैं, उनके लिए बनायेंगे जिस में आप सब एटीसीडेंट्स वगैरह बता सकें, अगर पब्लिक को नहीं बताने हैं तो ? सदन की एक कमेटी बना कर उसके सामने ये सब क्या मंत्री महोदय रखने के लिए तैयार हैं ?

श्री दिनेश सिंह : सेदन की तो कमेटियां बनी हुई हैं और आप उनके बारे में जानते भी हैं। पी० ए० सी० है, एस्टीमेट्स कमेटी है। वे इन सब बातों की जांच कर सकती हैं। इनके अलावा मैंने एक सुझाव रखा था। मेरा कहना यह है कि जो भी आप मुनासिब समझें, मैं उसको मंजूर कर लूंगा।

Shri S. R. Damani: According to me, the contract was cancelled as the party could not supply the goods. May I know whether the quantity purchased later on was purchased at a higher price or at a lower price?

Shri Dinesh Singh: I am sorry, I could not give the exact value of sulphur purchased thereafter. I have not got it at this stage, but I will be glad to give it to the hon. Member.

श्री अब्दुल गनी डार : लिमये जी ने सवाल किया था कि उस वक्त क्या यह सच नहीं है कि देश मे उसका भाव 45 रुपये के लगभग था और अगर यह सच है तो आपने 55 रुपये में क्यो खरीदा ? जवाब में मंत्री जी ने कहा कि हमने जब बाहर से खरीदा उस वक्त उसका रेट ऐसा ही था । मैं जानना चाहता हू कि इसका आर्डर देने से पहले क्या आपने यह देख लिया था कि क्या यह देश में ही अवेलेबल नही है, और सरकार के कामों के लिये काफी अवेलेबल नही है ? अगर नही देखा था तो क्यो नही देखा था ? फिर जब यहा पर इतना सस्ता था आपने महगा क्यो खरीदा ? अपने देश मे रेट इतना गिरा हुआ था तो फिर आपने 55 रुपये में क्यो खरीदा ? क्यों आपने इसकी इजाजत दी ?

[लिमये जी نے سوال کیا تھا کہ اس وقت کیا یہ سچ نہیں ہے کہ دیش میں اس کا بھاؤ ۴۵ روپئے کے لگ بھگ تھا اور اگر یہ سچ ہے تو آپ نے ۵۵ روپئے میں کیوں خریدا - جواب میں منتری جی نے کہا ہے کہ ہم نے جب باہر سے خریدا اس وقت اس کا ریٹ ایسا ہی تھا - میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کا آرڈر دینے سے پہلے کیا آپ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ کیا یہ دیش میں ہی اویلیبل نہیں ہے اور جرنل کے کاموں کے لئے کافی اویلیبل نہیں ہے - اگر نہیں دیکھا تھا تو کیوں نہیں دیکھا تھا - پھر جب یہاں پر اتنا سستا تھا آپ نے مہنگا کیوں خریدا - اپنے دیش میں ریٹ اتنا گرا ہوا تھا تو پھر آپ نے ۵۵ روپئے میں کیوں خریدا - کیوں آپ نے اس کی اجازت دی -]

श्री दिनेश सिंह : कुछ गलत फहमी हो गई है । हमारे देश में सल्फर की बहुत कमी है । हम इसको बहुत बड़ी तादाद मे बाहर से मगाते हैं । इस साल लगभग 6 लाख टन सल्फर बाहर से आएगा । इस वास्ते यह सवाल नही है कि हमारे देश मे सस्ता मिल रहा था और हमने नही लिया ।

Awards to Exporters

+

*1292. **Shri Yashpal Singh:**
Shri S. C. Samanta:
Shri S. R Damani:

Will the Minister of Commerce be pleased to state

(a) whether Government are considering a proposal to allow competition among exporters and to give awards; and

(b) if so, the main features of the proposal?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The proposal under consideration is to give a limited number of awards, in the forms of shields, for outstanding export effort A Committee will be set up to make recommendations for the awards. Exporters with outstanding export performance as well as to other institutions making significant contributions in the field of export promotion will be considered for awards.